महेश ग्रोवर से पहले, जे

अरुण पुरी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता आपराधिक विविध संख्या 2005 की 2166/एम

8 मई, 2007

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 499 और 500-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारितायाचिकाकर्ताओं के खिलाफ मानहानि का आरोप-याचिकाकर्ताओं ने एक लेख में नाथूराम गोडसे को आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में वर्णित किया और आरएसएस को अलग से एक ऐसे संगठन के रूप में वर्णित किया जिसने 'आत्म-धर्मी हिंदू राष्ट्रवाद' की सदस्यता ली -नाथूराम गोडसे आर. एस. एस. के सदस्य थे या नहीं, यह बहस का विषय है -इसे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए-ट्रायल मजिस्ट्रेट ने एक स्पष्ट निष्कर्ष देने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है कि आर. एस. एस. एक प्रतिष्ठित, देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है, जिसमें कोई दलील या सबूत नहीं है - विचारण न्यायालय किसी भी विवाद से निपटने के दौरान अपनी तटस्थता और व्यक्तिपरकता खोने का जोखिम नहीं उठा सकता -याचिकाकर्ताओं ने प्रकाशन में त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हुए एक स्पष्टीकरण भी जारी किया-ट्रायल मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ताओं को समन करने का आदेश देते समय शिकायत और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच करने में विफल रहे -याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया-शिकायत के साथ-साथ समन आदेश को रद्द कर दिया गया।

आयोजित, कि R.S.S. के सदस्य के रूप में नाथूराम गोडसे की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए। या नहीं, यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इस तरह का जवाब यहां विवाद के दायरे से परे है, लेकिन तथ्य यह है कि ऐतिहासिक और अभिलेखीय अभिलेखों के आधार पर आर. एस. एस. और हिंदू महासभा के संगठन के साथ उनके जुड़ाव पर हमेशा एक सक्रिय बहस होती थी। इसलिए, वास्तव में उन्हें आर. एस. एस. के सदस्य के रूप में संदर्भित करके अपमानजनक या मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, बाद के अंक में स्पष्टीकरण डालकर इस तथ्य का खंडन किया गया है।

(Para 29)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि लेख में कहीं भी आर. एस. एस. की भूमिका का वर्णन नहीं किया गया है और नाथूराम गोडसे के कृत्य का वर्णन करते हुए इसमें किसी भी प्रत्यक्ष, गुप्त या षड्यंत्रकारी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। समन आदेश जारी करने से पहले शिकायतकर्ता के नेतृत्व में ऐसे किसी भी आरोप और परिणामी साक्ष्य के अभाव में, इसे आर. एस. एस. के लिए अपमानजनक और मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है

(Para 31)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक लेख को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और एक पृथक अंश को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। न्यायालय को यह तय करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि लेख एक निष्पक्ष पाठक के मन पर क्या प्रभाव डालेगा और यदि इस संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो अपमानजनक लेख महात्मा गांधी के वर्तमान उत्तराधिकारियों को भी संदर्भित करता है, जिसमें शायद समाज के सभी और विभिन्न वर्ग और आज के राजनीतिक वर्ग शामिल हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक और गुटबाजी की प्रवृत्तियों को जारी रखा है-लेखक द्वारा मौजूदा स्थिति पर एक कहने वाली और सनकी टिप्पणी। इस तरह के लेख को शायद ही तब तक निंदनीय कहा जा सकता है जब तक कि एक पाखंडी समाज वास्तविकताओं पर नेल्सन की नज़र नहीं डालना चाहता।

(पैरा 32)

आगे अभिनिर्धारित किया कि शिकायत में या साक्ष्य में अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि आईपीसी की धारा 499 के अवयवों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आकर्षित करने के लिए पूरा किया गया है या कि लेख में इस तरह से लगाया गया आरोप या तो निंदनीय, या मानहानिकारक है।

(Para 40)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है जब उन्होंने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि आर. एस. एस. एक प्रतिष्ठित, देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है जो स्पष्ट रूप से उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर था। न्यायालय किसी भी विवाद से निपटने के दौरान अपनी तटस्थता और व्यक्तिपरकता खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। एक झुकाव या पूर्वाग्रह या यहां तक कि एक निष्कर्ष जो अनुचित है, वादियों के विश्वास को तोड़ देता है। शिकायत को पढ़ना और साक्ष्य का अवलोकन, जिसके आधार पर समन आदेश पारित किया गया है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला नहीं बनाता है और ट्रायल मजिस्ट्रेट ने शिकायत में किए गए कथनों और साक्ष्य या रिकॉर्ड की जांच नहीं करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ताओं को समन करना उचित था।

(Para 43)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के प्रावधानों के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का अनुरोध किया है और अनुरोध किया है कि 15 दिसंबर, 2003 की आपराधिक शिकायत संख्या 192-1, जिसका शीर्षक "मुकेश गर्ग बनाम अरुण पुरी और अन्य" है, और साथ ही इसके अनुसरण में पारित 13 अक्टूबर, 2004 के समन आदेश को भी रद्द किया जाए।

(2) लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका, "इंडिया टुडे" में प्रकाशित एक लेख, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1 प्रधान संपादक है, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 प्रकाशन निदेशक है और याचिकाकर्ता नंबर 3 संपादक, प्रिंटर और प्रकाशक है, ने प्रतिवादी

नंबर 2-शिकायतकर्ता को इस आरोप के साथ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध किया है क्योंकि इसकी सामग्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (इसके बाद 'आरएसएस' के रूप में संदर्भित) के लिए मानहानिकारक और अपमानजनक थी।

(3) इंडिया टुडे ने 18 अगस्त, 2003 के अपने अंक में "56 घटनाएं जिन्होंने भारत को बदल दिया" शीर्षक के तहत लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की।

विचाराधीन लेख, जो इस अंक के पृष्ठ 12-13 पर सीरियल नंबर 3 के साथ "गांधी की हत्या एक सपने की हत्या" शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः— "1948

20वीं सदी के महानतम विचारों में से एक को 30 जनवरी, 1948 को 5.03 पी. एम. पर मार दिया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने विरोध की अवधारणा को फिर से परिभाषित करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई, दिल्ली के बिड़ला हाउस से बाहर निकले और प्रार्थना सभा करने के लिए बगीचे की ओर चले गए। उस शाम उनका स्वागत करने वाले 300 लोगों में एक आरएसएस कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे भी थे, जिन्होंने अपने स्वचालित 9 मिमी बेरेटा से महात्मा की नाजुक छाती में करीब से तीन गोलियां चलाईं। "विभाजन के लेखक" को सलाम करने का यह उनका तरीका था। और यह राजनेताओं के बीच एक संत का अंत था, जो चरम, आत्म-धर्मी हिंदू राष्ट्रवाद की हिंसा में अहिंसा के सर्वोच्च दूत थे। राष्ट्रपिता गांधी की बार-बार उनके उत्तराधिकारियों द्वारा हत्या की जाएगी। गांधीवाद, वे जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, उन्हें एक ऐसे देश द्वारा पहले ही निरर्थक बना दिया गया है जिसने 1948 से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक लंबा सफर तय किया है। और गांधी ने पाठ्यपुस्तकों में शरण ली है, निश्चित रूप से उस जुनून में नहीं जिसने उनकी हत्या की। गोडसे के पोते-पोतियां अंदर और बाहर दुश्मनों का आविष्कार करना जारी रखते हैं, भयानक वास्तविकता की पुष्टि करते हुए; गांधी को मारने वाला विचार जीवित है-और फल-फूल रहा है। (जोर दें आपूर्ति की गई)

(4) उपरोक्त पुनरुत्पादित लेख और विशेष रूप से जोर दिए गए शब्दों से अपनी संवेदनशीलता को आहत पाते हुए, शिकायतकर्ता, जिसने खुद को आर. एस. एस. का सह जिला कार्यकर्ता होने का दावा किया और हिंदू शिक्षा समिति, भारत विकास परिषद और अधिवक्ता परिषद से भी जुड़ा हुआ था, ने याचिकाकर्ताओं को 10 सितंबर, 2003 को एक कानूनी नोटिस दिया और उन्हें पत्रिका के अगले अंक में बिना शर्त माफी प्रकाशित करने और आरएसएस के झूठे और तुच्छ आरोपों को वापस लेने के लिए कहा।

(5) याचिकाकर्ताओं ने नोटिस का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि उनका आरएसएस को बदनाम करने या कोई बदनामी करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार

किया। इसके अलावा, 6 अक्टूबर, 2003 के अंक में, पत्रिका में एक स्पष्टीकरण डाला गया था, जो इस प्रकार हैः –

"स्वतंत्रता दिवस के विशेष अंक में यह लिखा गया था कि नाथूराम गोडसे एक आरएसएस कार्यकर्ता थे (" 56 चीजें जिन्होंने भारत को बदल दिया ", 18 अगस्त) महात्मा गांधी की हत्या के समय गोडसे आरएसएस से जुड़े नहीं थे। गलती के लिए खेद है "।

(6) जवाब, इनकार और सुधार से संतुष्ट नहीं होने पर, शिकायतकर्ता ने 15 दिसंबर, 2003 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी (जिसे इसके बाद 'ट्रायल मजिस्ट्रेट' के रूप में संदर्भित किया गया है) के न्यायालय में यह शिकायत दायर की।

(7) उपर्युक्त शिकायत के अनुसरण में, शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक साक्ष्य में स्वयं और आर. एस. एस. के दो अन्य कार्यकर्ताओं से पूछताछ कराई और उनके बल पर, याचिकाकर्ताओं को तलब किया गया-13 अक्टूबर, 2004 के आदेश द्वारा आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए।

(8) याचिकाकर्ताओं ने इस शिकायत के साथ-साथ उसके अनुसरण में पारित समन आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. चीमा ने तर्क दिया कि जिस लेख के संदर्भ में इसे लिखा गया है, उसे पढ़ने पर उसे मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। आर. एस. एस. पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।संगठन जो इसे शिकायत करने का कारण दे सकता है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की जांच के लिए नियुक्त जांच आयोग, न्यायमूर्ति जे एल कपूर की रिपोर्ट का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य नहीं थे और उनका संगठन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों का अवलोकन उन्हें आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव से दोषमुक्त नहीं करता है और रिपोर्ट में ही संगठन को एक आतंकवादी हिंदू संगठन के रूप में संदर्भित किया गया है। इस विचार में, यह तर्क देने की मांग की गई थी कि लेख में कोई द्वेष नहीं था और शिकायत को पढ़ने से आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध होने का खुलासा नहीं होता है

(10) इसके बाद श्री चीमा ने यह तर्क दिया कि इस तथ्य से इनकार करने पर भी कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य नहीं थे, ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और किसी भी स्थिति में, एक संगठन जिसके लाखों सदस्य हैं, निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की सदस्यता स्थापित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि नाथूराम गोडसे उस संगठन के सदस्य थे या नहीं।

(11) अंत में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ सामान्य आरोपों को देखते हुए लेख के प्रकाशन के संबंध में जानकारी के किसी विशिष्ट आरोपण के बिना तलब नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, धारा 1 में दिखाई देने वाली 'संपादक' की परिभाषा और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक लेख प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका को उसके द्वारा अपराध किए जाने को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से चित्रित किया जाना चाहिए।

(12) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. पी. जैन ने जोरदार तर्क दिया कि इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शिकायत को रद्द करने से रोका गया है क्योंकि इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वह किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करता है। जहां शिकायत किसी अपराध के होने का खुलासा करती है और उस प्रश्न को उठाती है जिसका उत्तर केवल निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर दिया जा सकता है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने श्रीमती नागावा बनाम वीरन्ना शिवालिंगप्पा कोंजलगी और अन्य, (1) के. एम. मैथ्यू बनाम के. ए. अब्राहम और अन्य (2) और श्रीमती चंद धवन बनाम जवाहर लाई और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया (3).

(13) यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास पुनरीक्षण का एक वैकल्पिक उपाय था और तदनुसार, समन आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से उचित है। प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने भी जोरदार तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का आरएसएस से संबंधित होने का उल्लेख करना भी मानहानिकारक है।

(14) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(15) यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि यदि कोई शिकायत किसी अपराध के होने का खुलासा करती है, तो मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया को गति देने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर है और ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ करेगा।

(16) श्रीमती में। नागावा बनाम वीरन्ना शिवालिंगप्पा कोंजालगी और अन्य (उपर्युक्त) सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः-"इस न्यायालय के निर्णयों के एक लंबे समूह द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसी के समर्थन में साक्ष्य से संबंधित है और उसे केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। यह मजिस्ट्रेट का प्रांत नहीं है कि वह मामले के गुण-दोष या दोष-दोष की विस्तृत चर्चा करे और न ही उच्च न्यायालय इस मामले में अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में जा सकता है जो बहुत सीमित है। XX XX XX XX XX XX XX XX XX

यह सच है कि कोई प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने में मजिस्ट्रेट शिकायत के सामने या आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता के नेतृत्व में साक्ष्य में दिखाई देने वाली अंतर्निहित असंभवताओं को ध्यान में रख सकता है, लेकिन आरोपी की संभावना या दोषसिद्धि और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले की स्थापना के बीच सीमांकन की एक बहुत ही पतली रेखा प्रतीत होती है। मजिस्ट्रेट को मामले में एक निर्विवाद विवेकाधिकार दिया गया है और विवेकाधिकार का उपयोग उसके द्वारा न्यायिक रूप से किया जाना है। एक मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, यह उच्च न्यायालय या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए मजिस्ट्रेट के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करने या योग्यता के मामले की जांच करने के लिए नहीं है ,यह पता लगाने के लिए कि क्या शिकायत में आरोप, यदि साबित हो जाते हैं, तो अंततः अभियुक्त को दोषसिद्धि में समाप्त हो जाएगा। ये विचार धारा 202 के तहत एक जांच के दायरे और दायरे के लिए पूरी तरह से विदेशी हैं जो धारा 204 के तहत एक आदेश में समाप्त होता है। इस प्रकार

निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द या अलग किया जा सकता है -
(1) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज गवाहों के बयान को उनके अंकित मूल्य पर लिया गया है, वहां आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत में आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए गए अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं किया गया है; (2) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सके कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है; (3) जहां मजिस्ट्रेट द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, प्रक्रिया मनमाना और मनमाना है, जो किसी भी सबूत या सामग्री पर आधारित नहीं है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और (4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति या इसी तरह।

(17) उपर्युक्त सिद्धांतों को बाद के निर्णयों में भी सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुता द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैः -

1 हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाई और अन्य,
2 जनता दल बनाम एच एस चौधरी और अन्य,
3 भारत संघ और अन्य बनाम बी आर बजाज और अन्य,
4 रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल,
5 एच पी बनाम पृथ्वी चंद की स्थिति,
6 स्टेट ऑफ डब्ल्यू बी बनाम नारायण के. पटोदिया,

(18) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह जांच करे कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर अभियुक्त के विरुद्ध बिल्कुल कोई मामला नहीं बनाते हैं या नहीं या क्या शिकायत अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को शिकायत में दिए गए आरोपों को सूक्ष्म चश्मे के तहत यह निष्कर्ष निकालने के लिए रखना होगा कि क्या कोई अपराध बनाया गया है या नहीं।

(20) तत्काल मामले पर आते हुए, ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए लेख के अवलोकन से पता चलता है कि नाथूराम गोडसे को आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में वर्णित किया गया था और आरएसएस को अलग से ऐसे संगठन के रूप में वर्णित किया गया था जो "आत्म-धर्मी हिंदू राष्ट्रवाद" के अधीन था। ये वे शब्द हैं जो स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को आहत करते प्रतीत होते हैं।

(21) प्रत्यर्थी नंबर 2 शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि किसी व्यक्ति को आरएसएस से संबंधित होने के रूप में दिया गया संदर्भ अपने आप में मानहानिकारक है, कम से कम कहने के लिए अप्रिय है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में गर्व से खुद को आरएसएस का सदस्य होने का दावा किया है और संगठन के लिए भजन गाए हैं। अगर "आरएसएस के सदस्य" शब्द मानहानिकारक हैं, तो शिकायतकर्ता ने खुद पर आरएसएस के सेह जिला चालक की प्रशंसनीय भूमिका क्यों थोप दी? और पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र और मानव जाति की सेवा में एक सामाजिक, गैर-राजनीतिक, राष्ट्रवादी और देशभक्त संगठन के रूप में आरएसएस की प्रशंसा करने के लिए समान रूप से प्रशंसनीय शब्दों में घोषणा की, जिसमें पैंतीस हजार शाखाएं, दस लाख सेवक शाखाओं में शारीरिक और नैतिक शिक्षाएं सीख रहे हैं। वे सदस्य नहीं हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के साथ खुद को पहचानते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील के तर्क का कोई महत्व नहीं है।

(22) शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि यह पूरी तरह से ऊपर दिए गए लेख पर आधारित है जिसमें लेखक ने नाथूराम गोडसे को आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में संदर्भित किया है।

(23) इतिहास और इसकी ऐतिहासिक हस्तियां, जिन्होंने एक बार इस पृथ्वी को पार किया था और इस पर महान व्यक्ति के रूप में खड़े हुए थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक पहेली रहे हैं। इतिहास के नायक और खलनायक, उनके व्यक्तित्व, जुनून, कार्य, इस तरह के कार्यों और चूक के लिए मजबूरियां, जिन्होंने उन्हें अलग बना दिया, हमेशा शिक्षाविदों, इतिहासकारों और सिद्धांतकारों के बीच बुद्धिमान अटकलों का विषय रहे हैं, जो उन्हें ग्रे और ब्लैक सहित विभिन्न रंगों में चित्रित करते हैं और अपने पात्रों को एक वास्तविक और काल्पनिक स्पर्श देते हैं।

(24) नाथूराम गोडसे इससे अलग नहीं थे और तदनुसार, वे उन अध्ययनों के विषय रहे हैं जिन्होंने उनके अतीत को उजागर करने की कोशिश की और राष्ट्रपिता के कार्यों और हत्या के उद्देश्यों को समझने की भी कोशिश की। ऐतिहासिक और अभिलेखीय अभिलेखों पर आधारित ऐसी अटकलों के बीच, उनके और आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं।
(25) बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अदालत के समक्ष कुछ पुस्तकों के उद्धरण रखे जिनमें नाथूराम गोडसे को आरएसएस के साथ संबंध रखने के रूप में वर्णित किया गया है।याचिका में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः -

"पुस्तक = घर में निर्वासित
लेखक = आशीष नंदी
प्रकाशक = ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
पृष्ठ = 81...इस तरह की पृष्ठभूमि से ही हिंसक, चरमपंथी और पुनरुत्थानवादी राजनीतिक समूहों के कार्यकर्ता अक्सर आते हैं।
आश्चर्य की बात नहीं है कि 1929-30 में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक संक्षिप्त अवधि के बाद, नाथूराम लगभग बीस साल की उम्र में हिंदू महासभा, एक छोटे से राजनीतिक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्साही सदस्य बन गए।

स्वयं सेवक संघ, उस समय वस्तुतः अपने सभी प्रमुख पदों के साथ महासभा की एक सम-सैन्य शाखा थी

महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अत्यधिक रूप से दोनों समूहों ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के कारण का समर्थन किया और आत्मसम्मान के लिए हिंदू खोज को स्पष्ट करने की कोशिश की।
2 पुस्तक = गांधी और गोडसे-समीक्षा और ए

आलोचना
लेखक = कोएनराड एल्स्ट%

प्रकाशकः वॉयस ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
अध्याय = 2

पैरा = 2.4 पृष्ठ = 17,18 और 19 2.4 आरएसएस पर गोडसे भाइयों की गवाही
आरएसएस के साथ उनकी भागीदारी पर नाथूराम गोडसे का अपना संस्करण यहां दिया गया है।
29.1..
.... एन. गोडसेः मैंने गांधी की हत्या क्यों की, पृष्ठ 27
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
यह सच है कि उनके गुरु, वी. डी. सावकर ने आर. एस. एस. की हल्की अवमानना की थी, एक सर्वविदित तथ्य जिसने गोडसे के अदालत के बयान को विश्वसनीयता दी कि उन्होंने एच. एम. एस. के अध्यक्ष पद पर सावरकर के प्रवेश के समय आर. एस. एस. छोड़ दिया था। लेकिन तब, सावरकर का आरएसएस के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, जबकि गोडसे भाइयों ने अपने युवा दिनों में आरएसएस की बैठकों में समय बिताया था और इसके साथ एक करीबी संबंध विकसित किया था, जिसे अस्वीकार करना इतना आसान नहीं था।
इसलिए नाथूराम ने यह धारणा बनाने की कोशिश की कि आरएसएस का उनसे कोई लेना-देना नहीं है, बस इससे बचने के लिए

हत्या के बाद के कठिन महीनों में आरएसएस के लिए और अधिक परेशानी पैदा करना। गोपाल बताते हैंः "उन्होंने अपनी किताब में कहा है।

बयान कि उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस बहुत मुसीबत में थे। लेकिन उन्होंने आरएसएस नहीं छोड़ा
वास्तव में यहाँ कोई विवाद नहीं है। नाथूराम गोडसे ने कभी भी आरएसएस को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन वह हत्या से पहले के वर्षों में आरएसएस के ढांचे के भीतर काम नहीं कर रहे थे। वैचारिक रूप से वे अभी भी आर. एस. एस. के आदमी थे। यही कारण है कि जब वे फांसी पर चढ़ते थे तो उन्होंने आरएसएस की हर शाखा की बैठक का एक निश्चित हिस्सा राष्ट्रवादी आरएसएस गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूम ("मैं आपको नमन करता हूं, मातृभूमि से प्यार करता हूं, हमेशा") गाया।
3 पुस्तक-केसर फासीवाद
लेखक = श्याम चंद
प्रकाशक = हेमकुंट प्रकाशक
पृष्ठ = 64
गोपाल कहते हैं, "सभी भाई नाथूराम, दत्तात्रेय, गोविंद और मैं आरएसएस में थे। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर के बजाय आरएसएस में पले-बढ़े हैं। यह हमारे लिए एक परिवार की तरह था। नाथूराम आर. एस. एस. में एक 'बुधि कार्यकर्ता' (बौद्धिक कार्यकर्ता) बन गए थे उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस बहुत मुसीबत में थे। उन्होंने आरएसएस नहीं छोड़ा।

(26) यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने भी अपनी शिकायत में न्यायमूर्ति जे. एल. कपूर जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई लेना-देना नहीं है।

(27) रिपोर्ट के प्रासंगिक भागों को सामूहिक रूप से अनुलग्नक पी 10 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है जो गृह सचिव की रिपोर्ट का उल्लेख करता है जिसमें सरकार को आरएसएस और हिंदू महासभा के कार्यों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि नाथूराम गोडसे का कट्टर सावरकरवादी होना संभावित रूप से खतरनाक था, लेकिन रिपोर्ट में आरएसएस को संदेह का एक अनिच्छुक लाभ देते हुए कहा गया हैः-"19.44 आदेश, Ex 113, दिनांक 8 अगस्त, 1947 में, जो बॉम्बे गृह सचिव द्वारा जारी किया गया था, एक निर्देश दिया गया था कि R.S.S. के संचालन पर कड़ी नजर रखी जाए। और हिंदू महासभा संगठनों के।
19.45 ऐसा प्रतीत नहीं होता कि डी. आई. जी., सी. आई. डी. द्वारा आर. एस. एस. की कोई पृथक सूची तैयार की गई थी, और न ही यह सूची दर्शाती है कि इस सूची में जिन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं वे आर. एस. एस. के सदस्य थे, लेकिन यह दर्शाने के लिए सबूत हैं कि आर. एस. एस. के कई सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य थे। इस सूची में नाथूराम गोडसे के नाम हैं जिन्हें एक कट्टर सावरकरवादी के रूप में दिखाया गया है, एन. डी. आप्टे को संभावित रूप से खतरनाक के रूप में दिखाया गया है, जी. वी. केतकर को एक कट्टर सावरकरवादी और हिंदू सभा की गतिविधियों के पीछे दिमाग और प्रभावशाली के रूप में दिखाया गया है, एन. आर. अठावले को भी संभावित रूप से खतरनाक और कट्टर सावरकरवादी के रूप में दिखाया गया है, और डी. आर. बैज को भी संभावित रूप से खतरनाक और बिना लाइसेंस के हथियारों में व्यापारी के रूप में दिखाया गया है।
(28) उपरोक्त से, यह नहीं कहा जा सकता है कि नाथूराम गोडसे के आरएसएस के साथ जुड़ाव का भूत आयोग की रिपोर्ट द्वारा पूरी तरह से प्रयोग किया गया था।
(29) आरएसएस के सदस्य के रूप में नाथूराम गोडसे की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकालना या न निकालना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इस तरह का जवाब यहां विवाद के दायरे से परे है, लेकिन तथ्य यह है कि ऐतिहासिक और अभिलेखीय अभिलेखों के आधार पर संगठनों, यानी आरएसएस और हिंदू महा सहबा के साथ उनके जुड़ाव पर हमेशा सक्रिय बहस होती थी। तो, ipso उसे R.S.S. के सदस्य के रूप में संदर्भित करके। इसे अपमानजनक या अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, बाद के अंक में स्पष्टीकरण डालकर इस तथ्य का खंडन किया गया है।

(30) किसी भी स्थिति में, आरएसएस सहित कोई भी संगठन हमेशा उस अवधि की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिकता के साथ पैदा होता है, जो उस समय प्रचलित हैं। उस समय प्रासंगिक राजनीतिक और सामाजिक रूढ़ियाँ, जिन्हें उस विशेष समय में संगठन के रंग को धूमिल करने के लिए वर्जित माना जा सकता है, आज की तरह सच नहीं हो सकती हैं। इसलिए, यह कहना कि किसी विशेष संगठन से संबंधित व्यक्ति ऐसे संगठन की भूमिका का पता लगाए बिना और निर्धारित किए बिना मानहानिकारक है, एक चरम भ्रम होगा।

शिकायत में यह आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है कि लेख नाथूराम गोडसे को इस तरह का कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाली पहले से मौजूद साजिश का संकेत देता है।

(31) लेख की ओर लौटते हुए, इसमें कहीं भी आरएसएस की भूमिका का वर्णन नहीं किया गया है और नाथूराम गोडसे के कृत्य का वर्णन करते हुए इसमें किसी भी प्रत्यक्ष, गुप्त या षड्यंत्रकारी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है।
समन आदेश जारी करने से पहले शिकायत के आधार पर इस तरह के किसी भी आरोप और परिणामी साक्ष्य के अभाव में, इसे आरएसएस के लिए अपमानजनक और मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है

(32) इसके अलावा, एक लेख को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और एक अलग अंश को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। न्यायालय को यह तय करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि लेख एक निष्पक्ष पाठक के मन पर क्या प्रभाव डालेगा और यदि इस संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो अपमानजनक लेख महात्मा गांधी के वर्तमान उत्तराधिकारियों को भी संदर्भित करता है, जिसमें शायद समाज के सभी और विभिन्न वर्ग और आज के राजनीतिक वर्ग शामिल हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक और गुटबाजी की प्रवृत्तियों को जारी रखा है-लेखक द्वारा मौजूदा स्थिति पर एक कहने वाली और सनकी टिप्पणी। इस तरह के लेख को शायद ही तब तक निंदनीय कहा जा सकता है जब तक कि एक पाखंडी समाज वास्तविकताओं पर नेल्सन की नज़र नहीं डालना चाहता।

(33) आई. पी. सी. की धारा 499 'मानहानि' को परिभाषित करती है, जबकि इसकी धारा 500 अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। वही नीचे पढ़ा गया हैः -

"499 मानहानि-जो कोई भी, बोले गए शब्दों या पढ़ने के इरादे से, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है नुकसान पहुँचाने का इरादा रखना, या यह जानना या विश्वास करने का कारण होना कि इस तरह के आरोप से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए कहा जाता है, सिवाय इसके बाद के मामले को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए।

स्पष्टीकरण 1-यह किसी मृत व्यक्ति पर कुछ भी आरोपित करने के लिए मानहानि के बराबर हो सकता है, यदि आरोप से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा यदि वह जीवित है, और इसका उद्देश्य उसके परिवार या अन्य निकट रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत करना है।
स्पष्टीकरण 2-किसी कंपनी या किसी संघ या व्यक्तियों के संग्रह के संबंध में आरोप लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है।
स्पष्टीकरण 3-एक विकल्प के रूप में या विडंबनापूर्ण रूप से व्यक्त किया गया आरोप मानहानि के बराबर हो सकता है।
स्पष्टीकरण 4-कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा जाता है, जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के आकलन में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, या उसकी जाति या उसके चरित्र के संबंध में उस व्यक्ति के चरित्र को कम करता है, या उस व्यक्ति की साख को कम करता है, या यह विश्वास करने का कारण बनता है कि उस व्यक्ति का शरीर एक घृणित स्थिति में है, या आम तौर पर अपमानजनक माना जाता है।

मानहानि के लिए 500 की सजा-जो कोई भी दूसरे को बदनाम करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(34) आई. पी. सी. में मानहानि शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

इसका रूप "बदनाम" शब्द से निकला है। चैम्बर्स डिक्शनरी (डीलक्स संस्करण) के अनुसार "बदनाम" शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैंः "अच्छी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को छीनना या नष्ट करना; दुर्भावनापूर्ण बातें कहना; बुराई बोलना; झूठा आरोप लगाना"।

(35) "मानहानि" के अर्थों की गणना करते समय, "मानहानि" शब्द को "मानहानि, बदनामी, बदनामी या मानहानि" के रूप में परिभाषित किया गया है।

(36) लॉर्ड एटकिन के अनुसार, यह पता लगाने के लिए कि क्या मानहानि की गई है, इसके लिए परीक्षण यह देखना है कि क्या शब्द आम तौर पर समाज के सही सोच वाले सदस्यों के आकलन में शिकायतकर्ता को कम करते हैं।

(37) आई पी सी की धारा 499 में दिए गए मानहानि के अपराध का सार यह है कि आरोप या तो नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानने या यह विश्वास करने का कारण होने के कारण लगाया गया होगा कि इस तरह के आरोप से किसी व्यक्ति को नुकसान होगा।

(38) आई. पी. सी. में दिए गए मानहानि के अपराध का पहला स्पष्टीकरण यह है कि "यह मानहानि नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में कुछ भी आरोप लगाया जाए जो सच है यदि यह सार्वजनिक भलाई के लिए है कि आरोप लगाया जाना चाहिए या प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह जनता की भलाई के लिए है या नहीं, यह तथ्य का सवाल है।

(39) उपरोक्त के पिछले भाग में, यदि प्रकाशन को देखा जाता है और विशेष रूप से इस संदर्भ में कि इतिहासकारों के लिए एक उग्र बहस है, जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक पात्रों के पग-निशान का पता लगाने की कोशिश की है, तो कोई भी आरोप जो संभवतः उस सामग्री के आधार पर बनाया गया है जो यदि पूरी तरह से सच भी नहीं है तो सत्य के करीब है और निष्कर्ष सत्य के रूप में ही सत्य है; मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। "निष्पक्ष टिप्पणी" के सिद्धांत में यह शामिल है कि यदि कोई प्रकाशन जो मोटे तौर पर वास्तव में सच बोलता है और किसी भी व्यक्तिगत एजेंडे या प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो उसे संरक्षित किया जाएगा।

(40) मेरी राय में, शिकायत में या साक्ष्य में अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि आई पी सी की धारा 499 के घटकों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आकर्षित करने के लिए पूरा किया गया है या कि लेख में इस तरह से लगाया गया आरोप या तो निंदनीय, अपमानजनक या मानहानिकारक है।

(41) प्रक्रिया जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायत और उसके समक्ष प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य को पढ़ने के बाद खुद को संतुष्ट करना होगा कि वास्तव में अपराध किया गया है। वह अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया को गति देना एक गंभीर कार्य है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

तत्काल मामले में शिकायत को पढ़ने से किसी भी अपराध के होने का पता नहीं चलता है और सबूत बहुत कम हैं। सीडब्ल्यू3-पवन चौधरी, वरिष्ठ वकील, जिला न्यायालय, जगाधरी ने निम्नलिखित रूप में गवाही दी

"मुकेश ने मुझे बताया कि नाथूराम गोडसे कभी भी आरएसएस के साथ निकटता से जुड़े नहीं थे। नाथूराम गोडसे को आरएसएस का कार्यकर्ता कहने का कोई औचित्य नहीं है। मुकेश ने मुझे बताया कि इंडिया टुडे के मुख्य संपादक, संपादक और प्रिंटर ने आरएसएस की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर नाथू राम गोडसे के बारे में यह लेख प्रकाशित किया है।

(42) इसी तरह, सामान्य आरोपों को छोड़कर कि आरएसएस एक सामाजिक, गैर-राजनीतिक और देशभक्त संगठन है और इसके साथ नाथूराम गोडसे के जुड़ाव ने संगठन को बदनाम किया है, याचिकाकर्ताओं की आपराधिकता को स्थापित करने के लिए कोई सार नहीं है और शिकायत आईपीसी की धारा 500 के तत्वों को संतुष्ट नहीं करती है ।

(43) इसके अलावा, समन के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है जब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आरएसएस एक प्रतिष्ठित, देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है जो स्पष्ट रूप से उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर था। न्यायालय किसी भी विवाद से निपटने के दौरान अपनी तटस्थता और व्यक्तिपरक स्वभाव को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। एक झुकाव या पूर्वाग्रह या यहां तक कि एक निष्कर्ष जो अनुचित है, वादियों के विश्वास को तोड़ देता है। पैराग्राफ 18 में, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है, उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि आर. एस. एस. को शांति और युद्ध दोनों में संकट के समय देशवासियों की मदद करने के लिए एक देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। एक तीव्र देशभक्तिपूर्ण संगठन के रूप में इसके चरित्र को कभी भी गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। यह चरित्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ है जो शाखा की तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय पुनरुत्थान का कार्य है। यह मातृभूमि और उसकी स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्ण भक्ति की जन्मजात भावना को जगाता है।

(44) ट्रायल मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश के पैराग्राफ 21 में आगे कहा है कि "लेख के खाली अवलोकन से, ऐसा लगता है कि लेखक महात्मा गांधी की हत्या के 50 साल बाद भी उनकी हत्या के लिए आरएसएस पर विश्वास कर रहा है। संदर्भ में अपने मुख्य हत्यारे नाथूराम गोडसे के साथ आठ अन्य लोगों के मुकदमे के बाद महात्मा गांधी की हत्या के पचास वर्षों के बाद भी आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाना, 10 फरवरी, 1949 को विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया उसका फैसला और 10 फरवरी, 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण डी आप्टे से संबंधित पंजाब उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और 15 नवंबर, 1949 को अन्य पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, विशेष न्यायाधीश और अन्य दो अभियुक्तों को किसी भी तरह से आरएसएस को जिम्मेदार ठहराए बिना उच्च न्यायालय द्वारा वीर सावरकर को बरी करना, प्रेरित प्रतीत होता है।

(45) उपरोक्त, टिप्पणियां विद्वत विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं की गई थीं, जिसमें शिकायत में कोई अभिकथन नहीं था या समन आदेश के पारित होने तक उसके समक्ष उस प्रभाव का कोई सबूत नहीं था। इस प्रकार, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

(46) निष्कर्ष निकालने के लिए, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि शिकायत का पठन और साक्ष्य का अवलोकन, जिसके आधार पर समन आदेश पारित किया गया है, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मामला नहीं बनाता है और विचारण मजिस्ट्रेट ने शिकायत में अभिकथनों और अभिलेख पर साक्ष्य की जांच नहीं करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ताओं को समन करना न्यायोचित था।

(47) पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय की निश्चित राय है कि शिकायत किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है क्योंकि यह तथ्य कि क्या नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था, बहस और अटकलों का विषय है जिस पर विभिन्न लेखकों और इतिहासकारों ने राय दी है और यह भी कि ऐसे मुद्दों पर ऐसी सक्रिय और स्वस्थ बहस केवल आलोचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है जो आगे प्रबुद्ध दिमाग बनाने में मदद करती है, जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और यह भी कि पत्रिका के बाद के अंक में एक विशिष्ट इनकार किया गया है।

(48) इसलिए यह याचिका स्वीकार की जाती है और शिकायत के साथ-साथ समन आदेश को भी निरस्त कर दिया जाता है।

आर एन आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेनू बाला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा